

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी-सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 217/2022

घेवरराम पुत्र सगताराम व अन्य
बनाम
मूलचन्द पुत्र हरलाल वगैरा

दिनांक 27.04.2026

उक्त अपील राज० भू राजस्व अधि० 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बावड़ी (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन/प्रकरण संख्या 47/2022 में पारित आदेश दिनांक 19.04.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो० सं० 1 से 3-प्रार्थी-मूलचन्द वगैरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील बावड़ी के ग्राम विनायकपुरा स्थित अपने खातेदारी कब्जाकाशत की स्वतंत्र तहसील सुदा खसरा नम्बर 620, 620/2 एवं 632 की उल्लेखित रकबा भूमि की पक्की पत्थरगढ़ी करवाने का आग्रह किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर, तहसीलदार बावड़ी को वादग्रस्त खसरान का सीमांकन करते हुए पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने तथा वक्त पत्थरगढ़ी आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांत-अप्रार्थी सं० 1 से 6-घेवरराम वगैरा ने राज० भू-राजस्व अधि० 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांत श्री उम्मेदसिंह बावरला, रेस्पो० सं० 1 व 3 के अधिवक्ता श्री पुनीत जांगु, रेस्पो० सं० 2/1 व 2/3 के अधिवक्ता श्री ओमकारसिंह, रेस्पो० सं० 2/2 के अधिवक्ता श्री इन्दर विश्णोई एवं रेस्पो० सं० 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलांत के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो० सं० 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में

du
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर



रास्ते पर अतिक्रमण कर, आवागमन बंद करने हेतु आमदा है। इस कारण विधिविरुद्ध पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो० के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि आलौच्य प्रकरण में रेस्पो० के आवेदन पर दिनांक 24.3.22 को वादग्रस्त खसरान का सीमाज्ञान पडौसी खातेदारों को सूचित कर, उपस्थित मौतबिरान के सामने मुटाम लगा कर करवाया गया। मौके पर ख०नं० 620 एवं 632 का रकबा जमाबंदी में दर्ज रकबे से कम पाया गया। अपीलांत के ख०नं० 620/1 एवं रेस्पो० के ख०नं० 620 के मध्य सडक ख०नं० 620/3 रेस्पो० की खातेदारी भूमि के अन्दर है, जिसे अपीलांत अपनी बता रहे है। रेस्पो० द्वारा अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित सम्मन की ट्रेकिंग रिपोर्ट पेश की गई थी, जो सभी डिलीवर्ड होने से प्रोपर तामिल है। रेस्पो०—प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश बाद सीमांकन पत्थरगढी करवाने का पारित किया गया है। जो विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाने का आग्रह किया गया।



रेस्पो०सं० 4 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया गया। अपीलांत का कथन है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित सम्मन उसे प्राप्त नहीं हुए और अत्यंत जल्दबाजी में की गई कार्यवाही से उसे समुचित सुनवाई का अवसर नहीं मिला। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थी को प्रेषित रजिस्टर्ड सम्मन की डाक रसीदें व ट्रेकिंग रिपोर्ट मौजूद है, परंतु पत्रावली से यह भी साबित है कि अपीलाधीन कार्यवाही मात्र 20 दिन में कर संपूर्ण दी गई। इसके अलावा आलौच्य प्रकरण में अप्रार्थी सं० 7—तहसीलदार बावड़ी की रिपोर्ट/जवाब का अभाव पाया गया, जबकि यह आज्ञापक प्रावधान है। अपीलाधीन आदेश में वादग्रस्त ख०नं० 620, 620/2 व 632 का सीमांकन एवं पत्थरगढी का आदेश पारित किया गया है, जबकि हल्का पटवारी भवाद द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द सीमांकन दिनांक 24.3.22 ख०नं० 620 एवं 632 की ही है, जिसमें ख०नं०

du
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

620/2 तथा अप्रार्थी-अपीलांट की मौजूदगी का कोई उल्लेख नहीं है। इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, उपखण्ड अधिकारी बावड़ी (जोधपुर) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र/ प्रकरण संख्या 47/2022 अनवान मूलचन्द व अन्य बनाम घेवरराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2022 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरा की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पों तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर, उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु विधिसम्मत आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 27-4-26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।



dhc
27/4/26

(सुनिता चौधरी)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर